

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 अग्रहायण 30, 1943 शक सम्वत्

#### विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1203 / वि०स० / संसदीय / 99(सं)-2021 लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन में पुर स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2021–2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (२०२१–२०२२ का द्वितीय अनुपूरक) संक्षिप्त नाम अधिनियम, २०२१ कहलायेगा।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2022 ई0 को समाप्त होने वाले <sup>उत्तर प्रदेश राज्य की</sup> यर्ष वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा 8479,53,00,000 रुपये सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग का दिया जाना 8479,53,00,000 रुपये (रुपये आट हजार चार सौ उनासी करोड तिरपन लाख मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची (धारायें 2 और 3 देखें)

(धाराय 2 और 3 देख)									
2	 	3							
सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनिधक							
		(लाख स्पर्यो में)							
		विधान सभा द्वारा	राज्य	की समेकित	निधि योग				
		स्वीकृत		पर भारित					
 भाग	राजस्व :	172250.00			172250.00				
	पूंजी :	166000.00			166000.00				
गाग	राजस्व :	1000.00			1000.00				
र्गाण विभाग (संचार साधन-	पूंजी :	1.00			1.00				
ग (श्रम कल्याण)	राजस्व :				400000.00				
य प्रशासन विभाग	राजस्व :				10000.00				
ल्याण विभाग (दिव्यांगजन	राजस्व :	16700.00			16700.00				
रण एवं पिछड़ा वर्ग									
				i ki					
ल्याण विभाग(समाज	राजस्व :	67000.00			67000.00				
एवं अनुसूचित जातियों का									
भाग	राजस्व :				15000.00				
वेभाग	राजस्व :				2.00				
ग्रोग :	राजस्व :			-	681952.00				
	पूंजी :	166001.00		-	166001.00				
 म्हायोग :		847953.00		-	847953.00				
		सेवायें और प्रयोजन  माग राजस्व : पूंजी : गाग राजस्व : गांण विभाग (संचार साधन- पूंजी : गांण विभाग (संचार साधन- पूंजी : गांण विभाग (दिव्यांगजन राजस्व : गांण प्वं पिछड़ा वर्ग  कल्याण विभाग (समाज राजस्व : एवं अनुस्चित जातियों का  भाग राजस्व : प्वं अनुस्चित जातियों का  भाग राजस्व : प्वं अनुस्चित जातियों का  भाग राजस्व : प्वं अनुस्चित जातियों का	सेवार्ये और प्रयोजन निम्नर्लि विधान सभा द्वारा स्वीकृत भाग राजस्व : 172250.00 पंजी : 166000.00 पंजी : 1000.00 गण विभाग (संचार साधन- पंजी : 1.00 गण (श्रम कल्याण) राजस्व : 10000.00 गय प्रशासन विभाग राजस्व : 16700.00 ज्याण विभाग (दिव्यांगजन राजस्व : 16700.00 ज्याण विभाग (समाज राजस्व : 67000.00 प्वं अनुस्चित जातियों का भाग राजस्व : 2.00 विभाग राजस्व : 2.00 प्योग : राजस्व : 681952.00 पंजी : 166001.00	सेवायें और प्रयोजन निम्नलिखित धनर (लार विधान सभा द्वारा राज्य स्वीकृत भाग राजस्व : 172250.00 पृंजी : 166000.00 पृंजी : 1000.00 गण (श्रम कल्याण) राजस्व : 1.00 गण (श्रम कल्याण) राजस्व : 10000.00 गण (श्रम कल्याण) राजस्व : 16700.00 गण (य प्रशासन विभाग राजस्व : 16700.00 जल्याण विभाग (दिव्यांगजन राजस्व : 16700.00 जल्याण विभाग (समाज राजस्व : 67000.00 जल्याण विभाग (समाज राजस्व : 15000.00 विभाग राजस्व : 2.00 योग : राजस्व : 681952.00 पृंजी : 166001.00	सेवारें और प्रयोजन निम्नलिखित धनराशियों से अनिधक (लाख स्पयों में)    विधान सभा द्वारा स्वीकृत पर भारित पर भार भारित पर				

### उददेश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2021—2022 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2021—2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

> सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

#### UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 853/XC-S-1-21-57S-2021 Dated Lucknow, December 21, 2021

# NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Viniyog (2021-2022 Ka Dwitiya Anupoorak) Vidheyak, 2021" S introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 17, 2021.

# THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (SECOND SUPPLEMENTARY 2021-2022) BILL, 2021

#### A BILL

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2022.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Second Short title Supplementary 2021-2022) Act, 2021.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 8479,53,00,000 (Rs. eight thousand four hundred seventy nine crore fifty three lac only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2022 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.

Issue of Rs. 8479,53,00,000 out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the year 2021-2022

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2022.

Appropriation

### SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 2			3				
Grant/Serial Services and purposes		Sums not exceeding					
			(In lakhs)				
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total		
9 Power Department	Revenue	172250.00		172250.00			
		Capital :	166000.00	-	166000.00		
22 Sports Dep	partment	Revenue :	1000.00	-	1000.00		
	ks Department cations-Roads)	Capital :	1.00	-	1.00		
76 Labour De	partment (Labour Welfare)	Revenue :	400000.00	-	400000.00		
78 Secretariat	Administration Department	Revenue :	10000.00	-	10000.00		
	fare Department (Empowerme ndicapped & Welfare Of Classes)	nt Revenue :	16700.00	-	16700.00		
80 Social Wel	fare Department (Social Welfar of Scheduled Castes)	re Revenue :	67000.00	-	67000.00		
86 Information	Department	Revenue :	15000.00	-	15000.00		
92 Culture De		Revenue :		-	2.00		
	Total :	Revenue	601052.00		681952.00		
		Capital :	166001.00		166001.00		
	Grant Total :		847953.00	<b>II</b>	847953.00		

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary expenditure *Charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2021-2022.

The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 2021-2022) Bill, 2021 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA,  $Vitt\ Mantri.$ 

By order,

J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.